प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 07 – 14 अगस्त 2017 मूल्य पांच रूपए

नोटबंदी के दौरान 80 लाख की गाड़ी खरीदने वाला नेता चर्चा में

- भाजपा अध्यक्ष द्वारा गांधी के अपमान पर प्रदेश कांग्रेस की चुप्पी सवालों में
- नोटबंदी के दौरान भाजपा पर जमीन खरीद के आरोप लगाकर खुलासे से क्यों पिछे हटे सुक्खु

शिमला/शैल। वीरभद्र की सरकार और पार्टी के संगठन के बीच जो सवाल सरकार बनने के साथ शुरू हुआ था वह अब तक लगातार जारी है। हांलाकि पार्टी के लिये प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने इस टकराव को विराम देने के लिये दोनो पक्षों को कड़ी हिदायत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक न तो सुक्खु हटेंगे और न ही वीरभद्र। लेकिन शिंदे के जाने के बाद वीरभद्र ने फिर कहा कि संगठन के चुनाव जल्द हो जाने चाहिये। उनका निशाना फिर सुक्खु था लेकिन सुक्खु ने वीरभद्र के इस प्रहार पर कोई प्रतिक्रिया न देकर अनुशासन की हिदायत का पालन किया। परन्तु इसके बाद जब वीरभद्र ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक विवादित ब्यान दे दिया और फिर अपने ही ब्यान पर सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन वीरभद्र के इस विविादित ब्यान के बाद उभरा राजनीतिक बवाल अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बवाल को रोकने के लिये संगठन की ओर से कोई सामने नही आया है। यही नही वीरभद्र पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष सत्ती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर सार्वजनिक मंच से हर कुछ बोल दिया। जब लोकसभा में भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्ष गांठ के अवसर पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी गांधी के प्रति अपना और देश का आभार व्यक्त कर रहे थे उसी समय हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सत्ती गांधी को गाली दे रहे थे। सत्ती ने गांधी को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है शायद मोदी और शाह भी ऐसी भाषा की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस और सरकार पर गांधी के इस अपमान का कोई असर ही नही हुआ है। जबकि इस पर भाजपा को घेरा जा सकता था और यह भाषा सत्ती पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन सरकार और संगठन के टकराव के कारण इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नही मिली।

इस समय कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से भाजपा के खिलाफ कोई आक्रमकता देखने को नही मिल रही है। जबकि भाजपा पूरी आक्रमकता के साथ सरकार को विभिन्न माफियाओं का पर्याय प्रचारित करने में लगी हुई है। चुनाव सरकार की छवि पर लड़े जाते हैं इसमें संगठन की भूमिका यही होती है कि संगठन सरकार के कामकाज की छवि को आम आदमी तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इस समय सरकार की छवि पूरी तरह नाकारत्मक प्रचारित हो रही है और उसका कारगर जवाब देने वाला कोई सामने नही है। यहां तक कि संगठन में हर्ष महाजन जैसे वीरभद्र के अतिविश्वस्त अहम पदों पर बैठे हैं और विभिन्न निगमों/बार्डो में सरकार ने करीब पांच दर्जन लोगों को ताजपोशीयां दे रखी हैं। परन्तु आज इनमें से एक भी नेता भाजपा के हमलों का जवाब देने का साहस नही जुटा पा रहा है। बल्कि स्थिति तो यह बनती जा रही है कि इन ताजपोशीयां पाये कई नेताओं की कारगुजारीयों पर संगठन और सरकार को स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। इन दिनों नोटबंदी के दौरान एक ताजपोशी पाये नेता का करीब 80 लाख की गाड़ी खरीदा जाना आम चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि 79,80,000 का नकद भुगतान किया गया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कई चर्चाएं है। कल को जब ऐसे किस्से सामने आयेंगे तो उल्टा वीरभद्र को ही अपने इन विश्वस्तों को डिफैण्ड करना पड़ेगा।

संगठन में किसकी निष्ठाएं किसके साथ हैं इसको लेकर भी नये सिरे से सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि नोटबंदी के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु ने प्रदेश भाजपा पर यह संगीन आरोप लगाया था कि उसने नोटबंदी की आहट पाते ही शिमला और बिलासपुर में पार्टी कार्यालयों के नाम पर जमीन खरीदने में भारी निवेश किया है। लेकिन सुक्खु ने इस बारे में और कोई विस्तृत जानकारी सामने नही रखी थी सुक्खु के इस आरोप पर भाजपा की ओर से भी कुछ नही कहा गया था। लेकिन इस आरोप की सच्चाई आज तक प्रदेश की जनता के सामने नही आ पायी है। आज यह सवाल उठना स्वभाविक है कि सुक्खु ने इस आरोप का पूरा विकल्प जनता के सामने क्यों नही रखा? क्योंकि उसी दौरान हमीरपुर से कुछ लोगों ने सुक्खु के खिलाफ भी जमीन खरीद के आरोप लगाये थे और राज्यपाल से इस पर जांच करवाने का आग्रह किया था। बल्कि मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने भी इसमें जांच करवाने का दावा किया था। सुक्खु ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा दायर करने की बात की थी। बल्कि एक अन्य मामले में धूमल ने भी सुक्खु को मानहानि का नोटिस जारी किया था लेकिन यह सब कुछ थोड़े समय के लिये तो चर्चा में रहा है और उसके बाद सब अपनी – अपनी सुविधा के अनुसार खामोश हो गये। परन्तु आज चुनावों के मौके पर निश्चित रूप से जनता इस पर जवाब चाहेगी।

चुनावी वक्त पर तीसरे दलों की दस्तक के मायने

शिमला/शैल। प्रदेश विधान सभा के चुनाव इस वर्ष के अन्त में नवम्बर दिसम्बर में होने तय है। हिमाचल में अरसे से सत्ता कांग्रेस और भाजपा के बीच ही केन्द्रित रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि प्रदेश की जनता को इन दोनों में से किसी एक को चुनना उसकी विवशता रही है। क्योंकि इनका कोई राजनीतिक विकल्प टिक ही नही पाया। क्योंकि कोई भी जनता में अपनी विश्वसनीयता स्थापित ही कर पाया। तीसरे दल जनता को न तो यह समझा पाये कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने प्रदेश का कहां और क्या अहित किया और न ही इस पर आश्वस्त कर पाये की उनके पास विकल्प में क्या योजना है। आज प्रदेश एक प्रकार से कर्ज के चक्रव्यू में इस कदर उलझ चुका है कि कर्ज लेकर घी पीने की कहावत चरितार्थ हो रही है। प्रदेश की इस स्थिति के लिये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें कितना-कितना जिम्मेदार रही हैं इस पर तीसरे दलों की ओर से प्रदेश की जनता के सामने कभी कोई तस्वीर रखी ही नही है। जब कोई विकल्प बनने का दावा करने वाला इस मूल प्रश्न पर ही मौन रहेगा तो उसकी विश्वसनीयता का आकलन अपने आप ही हो जाता है।

आज हिमाचल में फिर कुछ दलों ने चुनावी दस्तक देने की घोषणाएं की है। इनमें ''राष्ट्रीय आजाद मंच'' ''राम'' ने प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। इस मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चण्डीगढ़ स्थित एक एडवोकेट सत्यव्रत हैं लेकिन हिमाचल की जिम्मेदारी 88 वर्षीय लै. जनरल पीएन हूण को सौंपी गयी है। जनरल हूण सेना के एक सम्मनित अधिकारी रहे हैं और अभी कुछ समय पहले तक वह केन्द्र सरकार के सलाहकार भी रहे हैं। सलाहकार का पद छोड़ने के बाद वह राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और भूतपूर्व सैनिकों के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हिमाचल का सेना में बड़ा योगदान और प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी काफी है। जनरल हूण ने पिछले दिनों जब शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया था तब उनका ज्यादा फोकस भूतपूर्व सैनिकों पर ही था। सूत्रों की माने तो मन्त्री कर्नल धनी राम शांडिल और पूर्व मन्त्री विजय सिंह मनकोटिया जनरल हूण के संपर्क में हैं। 88वर्षीय जनरल प्रदेश के भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों के सहारे कहां तक आगे बढ़ते हैं यह आने वाला समय ही बतायेगा।

इसी तरह एक लोक गठबन्धन पार्टी ने भी प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पांडे भारत सरकार के सचिव पद से निवृत होकर राजनीति में आये हैं और बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर हरे है। जस्टिस सी एस कर्णनन का खुलकर समर्थन किया है लोक गठबन्धन पार्टी ने। हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति पद से कार्यकाल पूरा होने के बाद जिस तरह की चिन्ता मुस्लिम समुदाय को लेकर व्यक्त की है लोक गठबन्धन पार्टी ने उसका खुलकर समर्थन किया है। किसानों की आत्महत्याओं से लेकर बैंको के लाखों करोड़े के एनपीए पर पार्टी ने पूर्व और वर्तमान सरकारों की नीतियों पर खुलकर प्रहार किया है। यह पार्टी जिस तरह अपने लिये एक बौद्धिक आधार तैयार कर रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इसका हिमाचल को लेकर क्या एजैण्डा है यह अभी तक सामने नही आया है।

आम आदमी पार्टी हिमाचल में विधानसभा चुनाव नही लड़ रही है क्योंकि वह अपने प्रदेश नेतृत्व को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नही हो पायी। क्योंकि यहां 'आप' सोशल मीडिया से बाहर जमीन पर कहीं नजर ही नही आ रही थी इसलिये इन्हें चुनाव न लड़ने का फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इस बार मायावती की बसपा प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। यह संकेत पिछले दिनों सेवानिवृत हुए डी जी पी पृथ्वीराज की अचानक सामने आयी राजनीतिक सक्रियता से उभरे हैं। पृथ्वीराज ने जिस तरह से सेवानिवृत होने के बाद कृष्णा नगर में एक पार्टी का आयोजन किया और उसके बाद अम्बेदकर की प्रतिमा के आगे संकल्प लिया है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं और बहुत संभव है कि बसपा उन्हें यहां की जिम्मदारी सौंपे। वामपंथी शिमला नगर निगम के महापौर और उपमहापौर पदों पर पिछली बार काबिज रह चुके हैं। इस नाते अब प्रदेश विधानसभा की सारी सीटों पर चुनाव लड़ना उनकी राजनीतिक आवश्यकता माना जा रहा है।

इस परिदृश्य में यदि यह सारे दल तीन प्रतिशत वोट भी ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश की राजनीति का खेल उल्टा कर रख देंगे। क्योंकि भाजपा के पूरे प्रयासों के बावजूद पार्टी को नगर निगम में अपने दम पर बहुमत नही मिल पाया है। फिर भाजपा में नेतृत्व के प्रश्न पर अस्पष्टता बनी हुई है। इस लिये इन तीसरे दलों की भूमिका को कम करके आंकना सही नही होगा।

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें

कार्यालय दूरभाष - 0177 - 2805015, मो. 8988587014, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल - shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट - www.shailsamachar.co.in

पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
- संपादक

स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान दें उद्यमीः राज्यपाल

शिमला/शैल। सीआईआई तथा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में बद्दी में आज 'ग्रीन कंपनीज' पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश को आर्थिक रूप से समृ) बनाने तथा विकास एवं समृद्धि में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिपेक्ष्य में सामाजिक सरोकार के अनेक ऐसे विषय हैं, जिनमें उद्योगपति सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमाचल में छः महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चलाया है, जिनमें पर्यावरण संरक्षण भी एक है।

राज्यपाल ने कहा कि सामुहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हरित आवरण को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए। इस तरह, वातावरण की शुद्धता के लिए स्वच्छता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज जागरूकता नहीं लाई गई तो भावी पीढ़ी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वैज्ञानिक हमें समय-समय पर चिंता से अवगत करवा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ईमानदारी से हमें इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने बीबीएनआईए के पर्यावरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की और आशा जताई कि भविष्य में भी एसोसिएशन हरित आवरण को बढ़ाने में सहयोग करेगी।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने झाड़माजरा में स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर,बीबीएनआईए के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा एसोसिएशन की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया।

राज्यपाल के सचिव तथा उद्योग विभाग के निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की जानकारी उपलब्ध करवाई।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजेश साबू, बीबीएनआईए के महासचिव वाई.एस गुलेरिया, सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष आई.एम. जे.एस सिधू तथा एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य सुषमा वर्मा को किया सम्मानित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने आवास होलीलाज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य कुमारी सुषमा वर्मा को सम्मानित किया। उन्होंने सुषमा वर्मा को पांच लाख रूपये का चैक तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षक के पद का प्रस्ताव भी दिया।

सुषमा वर्मा ने हाल ही में इंग्लेंड में आयोजित महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम में विकेटकीपर के तौर पर प्रतिनिधित्व किया था। सुषमा वर्मा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज पंचायत हिमरी के गढेरी गांव की रहने वाली है।

मुख्यमंत्री ने सुषमा वर्मा की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नवोदित प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं हैं। सुषमा ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रौशन किया है।

सुषमा वर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए आभार जताया। सुषमा ने बताया कि बचपन से ही उसका पुलिस में सेवा करने का सपना था जो अब पूरा हुआ है।

सुषमा वर्मा के साथ इस दौरान उनके पिता भोपाल वर्मा तथा गढेरी पंचायत के प्रधान जगदीश वर्मा भी थे।

पुलिस महानिदेशक सोमेश गोयल, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निदेशक अमरजीत सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं खेल विभाग की संयुक्त निदेशक सुमन रावत व अन्य भी इस मौके पर उपस्थित थे

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important date of tender are as under:-

Date of application	04-09-2017 upto 2.00 PM
Date of sale of tender form	04-09-2017 at 5.00 PM
Date of receipt of financial bid	05-09-2017 at 10.30 AM
Date of opening of financial bid	05-09-2017 at 11.00 AM

The tender shall be received up to 10.30 A.M. on 05-09-2017 and will be opened on the same day at 11.00 A.M in the presence of intending contractors or their authorised representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 04-09-2017.

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/Deposit at call/ Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office /Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur must accompany with each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Form No.	Cost of form
1.	C/o Balance work of link road from Behal to Swahan via Lakhala Km. 0/0 to 11/815 (SH:- Improvement of blind curve at RD 7/185 to 7/260 mi.e. Metalling and Tarring R/ Wall and U-Shape drain (Airtel Deposit).	Rs. 615231/-	Rs.12400/-	Rs.350		Three month
2.	Special Repair to Dhar Darobar Saraighat road Km. 0/ 0 to 9/0 (SH:- C/o V-Shape drain in Km. 2/0 to 4/400) Reliance Deposit	Rs. 382111/-	Rs.7800/-	Rs.350		Three month

Terms & Conditions:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2.Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of TIN Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.-2053/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने देने में केन्द्र करेगा हर संभव सहयोग

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से भेंट कर हिमाचल में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का आग्रह किया।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों का प्राकृतिक कृषि की ओर रूझान बढ़ा है और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस दिशा में ठोस पग उठाए हैं ताकि किसानों को इसका व्यापक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि एवं बागवानी दोनों विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि को लेकर सफल प्रयोग किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में सकारात्मक पहल की है। विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से इस पद्धति को किसानों तक पहुंचाकर जागरूकता लाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में उनके माध्यम से अनेक किसान मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को अपनाने के बारे में जागरूक किया गया है।

आचार्य देवव्रत ने बताया कि किसान वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक कृषि ही एकमात्र विकल्प है, जिसके माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके नियमित उपयोग से जहां उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम भी मिल सकेंगे। प्राकृतिक कृषि के उपयोग से फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और इससे गाय सीधा तौर पर कृषि से जुड़ सकेगी।

उन्होंने कहा कि रसायनों के अत्याधिक प्रयोग के कारण आज विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हुए हैं। अगर किसान प्राकृतिक कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो उन पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और बाहरी मण्डियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को देसी गायों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय को पालने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान भारी संख्या में इसकी ओर मुड़ रहे हैं।

राज्यपाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री को प्राकृतिक कृषि की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया।

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल के प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने की दिशा में विशेष रूचि लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके इस अभियान को हिमाचल में गति प्रदान करने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को निभाते हुए प्रदेश सरकार सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार की और संभावनाएं सृजित करने व युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण के उपरान्त बटमाना-जाबरी पंचायत में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में शिक्षा की दर उच्च है तथा सरकारी क्षेत्र में सभी को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना आरम्भ करने के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं भी आरम्भ की हैं, जिनमें व्यावसायिक कोर्स में उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए उपदान तथा स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है तथा आज यह क्षेत्र प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विकसित विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पहचान बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है तथा शीघ्र ही इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत महिला मण्डल को मुरम्मत कार्य या फर्नीचर की खरीद जैसे छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जाबरी में पशु पालन केन्द्र के लिए बजट प्रावधान किया गया है, जिसका निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन तथा जाबरी पाठशाला के जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ करने के लिए धनराशि जारी की जाएगी। पंचायत की घरोग-नालटा सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वित्तीय सहायता के प्रयोजन से नाबार्ड को भेजा गया है तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इसका निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ किया जाएगा। स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने जाबरी में बिजली बोर्ड के कार्यालय को खोलने का आश्वासन दिया।

विधानसभा चुनावों से पूर्व कुछ राजनैतिक दलों द्वारा द्वेषपूर्ण प्रचार पर गहरी चिन्ता जताते हुए मुख्यमंत्री ने धर्म, क्षेत्र तथा जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक जाति व धर्म को सम्मान करते हैं तथा हिमाचल एक संगठित राज्य है। लेकिन कुछ लोग अपने राजनैतिक हितों के लिए लोगों की भावना से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमें इन चालबाजियों को समझना होगा तथा प्रदेश की प्रगति व विकास को प्राप्त करने के लिए सबको संगठित होकर कार्य करते रहना है।

राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने गत साढ़े चार वर्षों के दौरान आरम्भ की गई ज्यादातर विकासात्मक परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में तीन आईटीआई खोली गई हैं और हाल ही में रोजगार मेले के आयोजन के दौरान निजी क्षेत्र में 250 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ पर हुआ 'युद्ध संग्रहालय' का लोकार्पण

शिमला/शैल। 'अगस्त क्रांति' के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ को देश में मनाए जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में लोगों को 9.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'यद्ध संग्रहालय' का लोकार्पण किया तथा दाड़ी में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को अपने सन्देश में कहा कि वह आजादी की लड़ाई के महान नायकों और उन सभी शूरवीरों को नमन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्तकर्ताओं से लेकर शूरवीर सैनिकों के बलिदान को याद करवाता है। उन्होंने कहा कि संग्रहालय राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बतरा, सौरभ का लिया तथा राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलदान करने वाले अन्य वीर सैनिकों के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 'मैं हिमाचल के शहीद हुए वीर पुरूष व वीरांगनाओं को नमन करता हूं और साथ ही उनके परिजनों को भी नमन करता हूँ जिनका स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में देश के लिए बराबर का योगदान रहा है।

कारगिल युद्ध के नायकों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों द्वारा कई बलिदान किए गए और हिमाचली भूमि के 54 वीर पुत्र शहीद हो गए और इस युद्ध संग्राहलय में उनके बलिदानों तथा उनकी वीरता को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए उल्लेखित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं होता, लेकिन कभी-कभार यह अनिवार्य हो जाता है और यह वह समय होता है, जब हमारे सैनिक अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए अपने अदमय साहस का परिचय देते हैं।

महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि 8 अगस्त, 1942 को मुंबई में उनके भारत छोड़ो भाषण में 'करो या मरो' के आहवान के कारण ही हम औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आन्दोलन भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

2190 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैले संग्रहालय के बाहरी भाग में जनरल जोरावर सिंह और वीरों के भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। अन्दर के भाग में वीरचक्र पुरस्कार विजेताओं, जमादार बन्धन राम तथा जमादार लाला की स्वर्ण पृष्ठ भूमि में दीवार पर लिखी गाथा को दर्शाया गया है। परमवीर चक्र तथा वीर चक्रों के विजेताओं में मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धान सिंह थापा, बैप्टन विक्रम बतरा, मेजर सुधीर वालिया, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार को शामिल किया गया है। संग्रहालय में देश के सभी परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो गैलरी के अलावा विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र, वीरचक्र इत्यादि सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों के पदक शामिल किए गए हैं।

संग्रहालय में 5X2 फुट आयात के अशोक स्तम्भ के अलावा पाकिस्तान से जीते गए झण्डे, रेजिमेंटल झण्डा, मीडियम मशीन गन इत्यादि को भी शामिल किया गया है।

हालांकि, भारत सरकार से मिग-21 तथा अन्य सैन्य शस्त्रों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य हेतु उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि 'राज्य शहीद स्मारक सेवा तथा विकास सोसाईटी' के प्रतिनिधियों को इस पुनीत व श्रद्धेय स्मारक की ओर ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया के साथ हार-जलाड़ी में दौलतपुर-हार-जलाड़ी-खार्ट सड़क पर बनेर खड़ पर 3.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 104 मीटर लम्बे पुल तथा कांगड़ा में 2.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33 केवी विद्युत सब स्टेशन की आधारशिलाएं रखी। यह विद्युत उप-केन्द्र कांगड़ा तथा इसके उपनगरों की आठ पंचायतों की 60 हजार की आबादी को बिजली उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने धर्मशाला में डल झील के सौन्दर्यीकरण, लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री कालेज मटौर तथा चामुण्डा मन्दिर परिसर में 5.87 करोड़ रुपये की लागत की एशियन विकास बैंक परियोजना की भी आधारशिला रखी।

उन्होंने धर्मशाला में 9.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित युद्ध संग्रहालय तथा करदयाणा की इक्कू खड्ढ पर 1.35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण भी किया।

उन्होंने 34,330 की वर्तमान जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए 17.43 करोड़ की लागत से कांगड़ा शहर के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के सम्वर्दधन का भी लोकार्पण किया। सन् 2046 तक इस योजना से लगभग 47,600 की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। बनेर खड्ढ से पानी उठाने के साथ इस योजना में 22 अग्निशमन हाईड्रैंट भी चलाए जाएंगे।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दी बोर्ड के अध्यक्ष से जुड़े मेरे वक्तव्य को मीडिया द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है जबकि मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि प्रदेश में भाजपा राज्य अध्यक्ष के मुकाबले राज्य गद्दी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के ज्यादा अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ही गद्दी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ तथा प्रदेश को इस समुदाय पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव गद्दी समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ बनाना भाजपा की पुरानी आदत है।

मानसून से हुआ 380 करोड़ रुपये नुकसान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मानसून से हो रहे नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को फील्ड स्टाफ को सक्रिय करने के निर्देश, ताकि सेब सीजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाया रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार के खतरे की चेतावनी तत्काल दी जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी सड़कों की युद्ध स्तर पर पुनर्बहाली सुनिश्चित बनाई जाए और वैकल्पिक मार्गों को क्रियाशील करने की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पाईप लाईनों की तुरन्त मुरम्मत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

वीरभद्र सिंह ने कृषि व बागवानी विभाग को भारी वर्षा के कारण हुए

नुकसान का आंकलन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट तुरन्त तैयार करनी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर इसे संकलित कर समय पर केन्द्र सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जल जनित रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए और ऐसा कोई मामला सामने आने पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने आपातकाल में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बचाव उपकरण व प्रशिक्षित श्रमशक्ति तैयार रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में त्वरित कार्रवाई दलों को क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सभी मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाए रखें तथा लोगों व सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब कोई मुख्य मार्ग अवरूद्ध हो तो पर्यटकों तथा आम लोगों को जिला मुख्यालय में ही रोका जाना चाहिए, ताकि उच्च मार्गों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पैदा न हो।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सभी जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि पूर्व चेतावनी के बाद ही जलाशय से पानी छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जलाशयों व बांधों से पानी छोड़ने के चौबीस घण्टे पूर्व चेतावनी व सतर्कता का उचित प्रकार से प्रचार सुनिश्चित बनाना होगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व विद्युत इत्यादि विभागों को कार्यों की तत्काल पुनर्बहाली के लिए 64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और आवश्यकता के अनुसार और राशि उपलब्ध करवाई जाएगी तथा कहा कि इस कार्य के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व व आपदा प्रबन्धन) तरूण श्रीधर ने इस दौरान वर्षा से हुए नुकसान बारे अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि गत सप्ताह के दौरान हुई भारी बारिश से प्रदेश में जनजीवन व सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान कुल 173 मौतें हुई, जिनमें 20 मौतें बाढ़, भू-स्खलन व बादल आदि फटने के कारण हुई है और शेष 153 मौतें सड़क दुर्घटना इत्यादि के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 124 भेड़ों बकरियां, गायों भैंसों व घोडों आदि पशुओं की भी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान प्रदेश में सड़क नेटवर्क व पुलों व कल्वर्ट को हुए नुकसान को 291 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि पेयजल व सिंचाई योजनाओं का नुकसान 80 करोड़ रुपये और विद्युत अधोसंरचना को 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुमानित तौर पर इस मानसून के दौरान 380 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

श्रीधर ने कहा कि दो-तीन दिनों के दौरान 280 सड़कें क्षतिग्रस्त व अवरूद्ध हुई है, जिनमें से आज 200 यातायात के लिए खोल दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 740 योजनाएं अवरू) हुई हैं, जिनमें से 540 को पुनर्बहाल कर दिया गया है।

निदेशक बागवानी ने इस अवसर पर बताया कि सेबों की पेटियों की ढुलाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और अब तक विभिन्न मण्डियों को 19 लाख से अधिक सेब की पेटियां भेजी जा चुकी हैं।

आईएमडी के प्रतिनिधि ने प्रदेश में हुई बारिश के बारे अवगत करवाया तथा कहा कि आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश की संभावना है।

मुख्यमंत्री राहत कोष की ऑनलाईन वैब-एप्लीकेशन हुई शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष की ऑनलाईन वैब-एप्लीकेशन http://cmhimachal.nic.in का शुभारम्भ किया। इससे मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाईन अंशदान किया जा सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में किए जाने वाले अंशदान में वृद्धि होगी। इस कोष को सामाजिक एवं नागरिक केन्द्रित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अब कोई भी व्यक्ति किसी भी समय नैटबेंकिंग अथवा क्रेडिट/डैबिट कार्ड के माध्यम से अंशदान कर सकेंगे। इस वैब-एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र की स्थिति का ऑनलाईन पता लग पाएगा। जरूरतमंदों की सुविधा के लिए यह प्रावधान भी किया गया है कि वे प्रदेश भर में स्थित लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष से ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र देकर सहायता के लिए भी आग्रह कर सकेंगे।

इस वैब-एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा तैयार किया गया है। हि.प्र.राज्य सहकारी बैंक के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वतंत्रता दिवस पर मेधावी छात्रों को शिक्षा विभाग बांटेगा 10000 लैपटॉप

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग राजीव गांधी डिजिटल छात्र योजना के तहत मार्च, 2017 में हुई दसवीं तथा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा के मेधावी छात्र व छात्राओं को 10 हजार लैपटॉप व 260 नेटबुक वितरित करेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 15 अगस्त, 2017 को जिला शिमला के रामपुर बुशैहर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लैपटॉप व नेटबुक के वितरण का शुभारम्भ करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2017-18 तक मेधावी विद्यार्थियों को 82.08 करोड़ रुपये की लागत के 42500 लैपटॉप व 471 नेटबुक प्रदान किए गए हैं, जिनमें इस वर्ष के 10000 लैपटॉप भी शामिल हैं। इसके लिये सभी पात्र छात्र विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध फार्म भरकर जिला के संबंधित उप-निदेशक के पास जमा करवाऐं।

खाद्य सामग्री न मिलने पर निगम से संपर्क करने की सलाह

शिमला/शैल। हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के समस्त राशन कार्ड धारक जो हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, को यदि किन्हीं कारणों से उचित मूल्य की दुकानों पर कोई खाद्य सामग्री उपलब्धा न हो तो उस स्थिति में राशन कार्ड धारक निगम के मुख्यालय में उनके सहायतार्थ स्थापित दूरभाष संख्या 0177-2621583 पर इसकी उपलब्धता न होने बारे तुरन्त सम्पर्क कर सकते हैं। निगम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये शीघ्र इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।

शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है ..... चाणक्य

सम्पादकीय

यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ यही प्रतिबद्धता है तो...

भ्रष्टाचार के खिलाफ देश जे.पी. आन्दोलन से लेकर अन्ना आन्दोलन तक कई जनान्दोलन देख चुका है। हर आन्दोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है यह भी एक सत्य है। प्रधानमन्त्रियों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हर वक्त अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिये कानून में सक्षम प्रावधान हैं। इन प्रावधानों से आगे बढ़कर राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना तक कर दी गयी है। लोकायुक्त की तर्ज पर ही केन्द्र में लोकपाल की स्थापना की जा रही है। संसद और विधानसभाओं में बैठे जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आये आपराधिक मामलों को एक वर्ष भीतर निपटाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालतों को बहुत पहले जारी कर चुका है। बल्कि इन निर्देशों के परिणामस्वरूप ही फॉस्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये गये हैं। लेकिन क्या इस सबके बावजूद भ्रष्टाचार रूक गया है या इसके मामलों में कोई कमी आयी है? इस सावल का जवाब तलाशते हुए उत्तर लगभग नकारात्मक ही निकलता है और इसी से यह सोचने जानने की आवश्यकता आ खड़ी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार में कमी क्यों नही आ रही है।

अभी सर्वोच्च न्यायालय ने नीरा यादव के मामलें में फैसला सुनाते हुए अपनी चिन्ता में इसके लिये समाज की सोच और उसके बदलते संस्कारों को इसके लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना है। इन्ही बदलते सामाजिक संस्कारों/सरोकारों के कारण ही हम अत्यधिक उपभोक्तावाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो इसके खिलाफ सामूहिक आन्दोलन तक का आहवान किया है। यह सामूहिक आन्दोलन चाहिये भी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस आन्दोलन का स्वरूप क्या हो और यह कहां से शुरू हो। समाज के संस्कार उसको दी जाने वाली शिक्षा से बनते हैं यह एक स्थापित सत्य है। लेकिन आज देश की बिडम्बना यह है कि हम अभी तक एक शिक्षा नीति और एक ही पाठयक्रम पर सहमत नही हो पाये हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी स्कूलों को गरीबों के लिये शिक्षा का साधन मान लिया है और उच्च/संपन्न वर्ग के लिये नीजि स्कूलों को जब अमीर और गरीब के लिये शिक्षा के साधनों का पैमाना इस तरह से अलग - अगल हो जायेगा तो स्वभाविक है कि एक समान संस्कार नही बन पायेंगें। आज नीजि क्षेत्र के लिये शिक्षा एक बड़ा व्यापार बन गयी है। क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिये। स्वभाविक है कि जिसकी आवश्यकता समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को होगी वह व्यापार का उतना ही सबसे बड़ा क्षेत्र बन जायेगा। शिक्षा में नीजि क्षेत्र के बढ़ते दखल के खिलाफ यू पी ए शासन के दौरान आज केन्द्र में सतारूढ़ भाजपा का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक भी आन्दोलन कर चुका है। देश का छात्र वर्ग शिक्षा में नीजि क्षेत्र के बढ़ते दखल के खिलाफ एकमत है क्योंकि नीजि क्षेत्र के शिक्षण संस्थान आज शिक्षा नही बल्कि व्यापारिक प्रतिष्ठान बन कर रह गये हैं। नीजिक्षेत्र में चल रहे स्कूलों से लेकर उसके विश्वविद्यालयों तक यही व्यापारिक स्थिति बनी हुई है। शिक्षा में नीजिक्षेत्र का बढ़ता दखल और उसकी बढ़ती मनमानी आज चिन्ता का सबसे बड़ा कारण हैं क्योंकि शिक्षा संस्कार का मूल होती है और शिक्षा में बढ़ते व्यापारवाद के कारण ही अत्यधिक उपभोक्ता संस्कृति हमारी मानसिकता बनती जा रही है। क्योंकि नीजिक्षेत्र द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में सबसे बड़ी भूमिका वहां खर्च किये जाने वाले पैसे की है। क्योंकि वहां दी जाने वाली भारी भरकम फीस एक स्टटेस सिंबल बन चुकी है। ऐसे में जब कोई किसी भी तरह का व्यवसायिक प्रशिक्षण ''डाक्टर, वकील, इन्जिनियर'' नीजिक्षेत्र से लेकर आता है तो नौकरी में आते ही उसकी मानसिकता सेवा भाव की न होकर केवल व्यापारिक होकर रह जाती है। क्योंकि शिक्षण/प्रशिक्षण के दौरान किये हुए खर्च का दस गुणा बसूल करना होता है। इस खर्च वसूल करने की मानसिकता के चलते उसका हर सामाजिक रिश्ता संबध कवेल पैसा होकर रह जाता है। यही पैसे की मानसिकता आगे चलकर अपराध और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आज समाज को इस पैसा केन्द्रित मानसिकता से बचाने का केवल एक ही मार्ग शेष है और वह है पूरे देश में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक हर सतर के लिये एक ही पाठ्यक्रम और एक ही फीस। संस्थान चाहे सरकार का हो या नीजिक्षेत्र का सबके ऊपर यह नियम एक समान लागू होना चाहिये। शिक्षा में नीजि क्षेत्र सेवाभाव से नही वरन् बाजार भाव से प्रवेश कर रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नीजिक्षेत्र के बढ़ते दखल को रोकना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब शिक्षा व्यापारिक मानसिकता से संचालित होगी तो उसका अन्तिम परिणाम केवल उपभोक्तावाद ही होगा।

इस परिदृश्य में देश के प्रधानमन्त्री से लेकर सर्वोच्च न्यायपालिका से यह आग्रह है कि यदि वास्तव में ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर हैं तो इस दिशा में तुरन्त प्रभाव से कदम उठाने होंगे। शिक्षा के बाद चुनाव के क्षेत्र में भी इसी तरह के कदम की आवश्यकता है उस पर अगले अंक में चर्चा करूंगा।

बागवानी विकास परियोजना बागवानी क्षेत्र में लाएगी बड़ा बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने तथा मण्डी कार्य-नीति में बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से 1134 करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी बागवानी विकास योजना को लागू करने की पहल की है। यह परियोजना विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 80 अनुपात 20 में कार्यान्वित की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश को पहले ही देश के फल राज्य के रूप में जाना जाता है। राज्य के लोगों की खुशहाली तथा सकल घरेलू उत्पाद में फलोत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार ने बागवानी विकास के लिए सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म योजनाएं बनाई हैं।

हिमाचल प्रदेश बागवानी के क्षेत्र में पहाड़ी राज्यों में म डल राज्य के रूप में जाना जाता है। कठिन भोगौलिक परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश के बागवान, बागवानी को एक मुख्य व्यावसाय के रूप में अपना रहे हैं, और यह व्यावसाय अब ग्रामीण क्षेत्रों की आय का साधन बन चुका है। यही कारण है कि इस छोटे से राज्य में लोगों को फल, पुष्प और सब्जी उत्पादन से लगभग 7600 करोड़ रुपये की सालाना आय हो रही है।

यहां पर यह बताना उचित होगा कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान देश में आयातित फलों के कारण सेब को भीषण मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निदान हेतु हमारी सरकार फलों की पैदावार व गुणवत्ता बढ़ाने के लिये विश्व बैंक द्वारा पोषित बागवानी विकास परियोजना को क्रियान्वित कर रही है ताकि बागवानों की उत्पादकता तथा फलों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके और प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के क्षेत्रों में फलों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए पानी उपलब्ध क्षेत्रों में चिन्हित कलस्टरों में सेब व अन्य फलों के क्नोनल रुट स्टॉक पर आधारित उच्च धनत्व बागानों की स्थापना कर फलों के उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में बढ़ौत्तरी सुनिश्चित बनाई जाएगी।

परियोजना के अंतर्गत समस्त कार्य चिन्हित क्लस्टरों में कार्यान्वित किए जायेंगे, जिसमें मुख्यतः सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु वर्षा के पानी व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जल का उचित दोहन करके सामुदायिक टैंको का निर्माण किया जाएगा ताकि बागवानों द्वारा उच्च घनत्व पौधारोपण (high denisity plantation) पर स्थापित बागीचों को उचित सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके।

राज्य में बागवानी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये परियोजना में सामुदायिक सिंचाई सुविधाएं विकसित करने का विशेष प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत लगभग 19560 हेक्टेयर भूमि को परियोजना में शामिल किया जाएगा तथा गर्मियों व पौधों की प्रारम्भिक अवस्था के दौरान पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाएगी।

इसके साथ एचपीएमसी तथा बागवानी विभाग की विधायन इकाईयों को अपग्रेड कर इनका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। प्रदेश में फलों व सब्जियां के विपणन की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु परियोजना के अंतर्गत 16 स्थानों पर स्थापित कृषि उपज मण्डियों को स्तरोन्नत करके आधुनिक तकनीकयुक्त किया जाएगा तथा प्रदेश के दो अन्य स्थानों पर नई आधुनिक मण्डियों की भी स्थापना की जाएगी ताकि बागवानों को फलों व सब्जियों के विपणन की उचित सुविधा प्राप्त कर उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

किसानों व बागवानों को अत्याधुनिक मण्डियों के माध्यम से बाहरी मण्डियों में उनके उत्पादों के बाजिब दाम उपलब्ध होंगे। निश्चित तौर पर बागवानी विकास योजना आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र की दशा व दिशा में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगी।

स्वतंत्रता के 70 वर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था:70 वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पिछले 70 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इनमें संकट के वर्ष 1966, 1981 तथा 1991 और भारत का आर्थिक संकट से विश्व के सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवथा के रूप में उभरना शामिल है।

वर्ष 1965 में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति दबाव में थी। 1966 के आते-आते हमारा विनिमय भंडार निचले स्तर पर आ गया था। मार्च 1966 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 200 मिलियन डालर का प्रबंध किया। अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप घरेलू मूल्यों को लाने के लिए 36.5 प्रतिशत रूपये का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात स्पर्द्धा बढ़ सके। जो अमरीकी डालर 4.75 रूपये के बराबर था वह 7.50 रूपये बढ़ गया और पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 13.33 रूपये से बढ़कर 21 रूपये हो गई। सरकार ने पंचवर्षीय योजना में अवकाश की घोषणा की। दो वर्षों के सूखे, दो युद्ध और रूपये के अवमूल्यन के कारण अर्थव्यवस्था को लड़खडाती देख तीन वार्षिक योजनाओं के पक्ष में चौथी पंचवर्षीय योजना का परित्याग कर दिया गया। वार्षिक योजनाओं का निर्देश विकास था और इनमें निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक परिसंपत्तियों के कारगर उपयोग की तलाश पर बल दिया गया। अवमूल्यन असफल रहा, उसे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। अपेक्षित विदेशी सहायता नहीं मिली।

1979-80 में नाटकीय तरीके से भुगतान संतुलन की स्थिति में परिवर्तन आया। जो मुद्रा स्फीति 1978-79 में तीन प्रतिशत थी वह 1979-80 में 22 प्रतिशत हो गई। आयातित पेट्रोल और उर्वरकों की ऊंची कीमतों के कारण व्यापार की बाहरी शर्ते खराब हो गई। व्यापार घाटा बढ़ गया। सरकार ने अप्रत्याशित रूप में घाटे का वित्तपोषण किया। 1981 में लघु अवधि के चक्रीय संतुलन को पूरा करने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पूरक वित्तीय सुविधा (सीएफएफ)के अंतर्गत स्वीकृत 500 मिलियन एसडीआर में से 266 मिलियन एसडीआर प्राप्त किया। सरकार ने पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वकर, इस्पात, खाद्य तेल, अलौह धातु के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति बहाल करने की रणनीति अपनाई। सरकार ने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया कि वह अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष की विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत 1.1 बिलियन एसडीआर का लाभ नहीं उठायेगी। उस समय की ऊंची मुद्रा स्फीति और भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति से निपटने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 1966 और 1981के कार्यक्रमों ने मदद दी। इन कार्यक्रमों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सफलता मिली। भारत ने 1990 के दशक में ढांचागत जटिलताओं और अर्थव्यवस्था में संतुलन के साथ प्रवेश करते हुए पांच प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद वृहद आर्थिक असंतुलन की घोषणा कर दी। 1991 में भुगतान संतुलन संकट में अनेक प्रतिकूल घरेलू बाहरी घटनाओं ने योगदान दिया। इस संकट से व्यापक सधार का कार्यक्रम उभरा। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष कार्यक्रम का समर्थन था और इसे कारगर तरीके से लागू किया गया।

27 अगस्त 1991 को भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से 18 महीने के लिए 1656 मिलियन एसडीआर के बराबर राशि की मांग की। समायोजन की इस रणनीति से जुलाई 1991 में स्थिरता के कदम उठाये गये। इन कदमों में विनिमय दर का 18.7 प्रतिशत अवमूल्यन और ब्याज दरों में वृद्धि सहित मौद्रिक नीति को कठोर बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य विश्वास बहाल करना और लघु अवधि पूंजी बाह्यप्रवाह की स्थिति को बदलतना था। वित्तीय मजबूती और

ढाचागत सधार के स्तभ पर कार्यक्रम बनाये गये। अनेक प्रकार से 1991,92 के आईएमएफ कार्यक्रम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण को सुनिश्चित किया।

वर्ष 2007 में आए वैश्विक वित्तीय संकट ने 2008 में विकराल रूप ले लिया। अनेक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान धराशायी हो गए। भारतीय स्टाक बाजार में मूल्य की दृष्टि से 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ। विदेशी पोर्टफोलियों निवेश में कमी आई और डॉलर के 50 रूपये प्रति डॉलर पर पहुंचने के साथ रूपये के मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी आई। यह धारणा गलत साबित हुई कि भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम से कोई जुड़ाव नहीं रखती। 7 दिसम्बर 2008 और 2 जनवरी 2009 दो पैकेजों के माध्यम से वित्तीय गति प्रदान की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक सहजता और तरलता बढ़ाने के अनेक कदम उठाये। इनमें नकद सुरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और महत्वपूर्ण नीति दरों में कमी शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली से धन उपलब्ध करना था।

वैश्विक संकट से विश्व में पहले उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। वित्तीय और मौद्रिक नीतियों से अर्थव्यवस्था को गति दी गई और विकास दर संकट पूर्व स्तर पर आ गई। आवक पूंजी बढ़ने लगी और वित्तीय बाजारों की सेहत अच्छी होने लगी। अनुमान व्यक्त किया गया कि वृद्धि दर 2009-10 के 6 3/4 से 2010-11 में 8 प्रतिशत हो जायेगी। भारत के सामने पूंजी प्रवाह प्रबंधन की चुनौती आई और इस दिशा में हस्तक्षेप किया गया ताकि विनिमय दर के उतार चढ़ाव को कम किया जा सके।

8 अक्टूबर 2016 को भारत के वित्त मंत्री ने फंड बैंक वार्षिक बैठकों के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) को संबोधित किया और 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि, 372 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार, (-) 1.1 प्रतिशत चालू खाता घाटा और 5.05 प्रतिशत मुद्रा स्फीति दर के साथ भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया। सरकार ने वित्तीय मजबूती, निजी क्षेत्र को कम लागत पर ऋण देने और मूल्य स्थिरता का संकल्प व्यक्त किया। सब्सिडी सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया और तेल सब्सिडी को आधार से जोड़कर सब्सिडी के बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया गया। सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति बनाई और 2016-2021 अवधि के लिए +/-2 स्तर के उतार चढ़ाव के साथ चार प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य तय किया। कर सुधारों में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) मील का पत्थर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 70 वर्ष की कहानी यह बताती है कि भारत आईएमएफ कार्यक्रम वाले देश से आगे बढ़कर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है। *** वी. श्रीनिवास**

भारत का बदलता परिवहन परिदृश्य

नितिन गड़करी

किसी भी देश की प्रगति का व्यक्यिों की आवाजाही और माल की ढुलाई से संबंधित उसकी दक्षता से गहरा संबंध है। अच्छी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन केन्द्रों और बाजार के बीच अनिवार्य संपर्क उपलब्ध कराते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। यह देश के एकदम दूरदराज के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कारक भी है।

दुनिया के सबसे विशाल परिवहन नेटवर्क्स में से एक होने के बावजूद, भारत का परिवहन नेटवर्क लबे अर्से से यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत धीमी रफ्तार और अकुशलता से ग्रसित रहा। इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां रहीं। दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर परिवहन नेटवर्क की पर्याप्त पहुंच का अभाव रहा। राजमार्ग संकरे, भीड़भाड़ वाले और खराब रख-रखाव वाले रहे, जिनकी वजह से यातायात की गति धीमी रहती थी, बहुमूल्य समय की हानि होती थी और प्रदूषण का भारी दबाव रहता था। इनकी वजह से आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती हैं। बहुत अधिक मात्र में माल ढुलाई सड़क मार्ग के जरिये होती है, हालांकि यह साबित हो चुका है कि यह माल ढुलाई का सबसे महंगा साधन हैं और इससे प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में ज्यादा किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, लेकिन उसका नेटवर्क धीमा और अपर्याप्त है। जबकि जल मार्ग, जो परिवहन के तीनों साधनों में से सबसे किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, बड़े पैमाने पर अल्प विकसित है। इस घाटे वाले म डल मिक्स के परिणामस्वरूप लाजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हमारी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं

हालांकि पिछले तीन-चार वर्षों से इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ है। सरकार ने देश में ऐसी विश्वस्तरीय परिवहन अवसंरचना का निर्माण करने को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी है, जो किफायती हो, सभी को आसानी से सुलभ हो सके, सुरक्षित हो और ज्यादा प्रदूषण फैलाने का कारण भी न बने और जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्वदेशी सामग्री पर निर्भर हो। इसमें विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उपलब्ध मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना, नई बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और इस कार्य में सहायक विधायी फेमवर्क को आधुनिक बनाना शामिल है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी तथा ऐसी साझेदारी के लिए समर्थ बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना और उसे प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का महज दो प्रतिशत अंश है,लेकिन वह यातायात के 40 प्रतिशत भार का वहन करता है। सरकार राजमार्गों की लंबाई और गुणवत्ता,दोनों के संदर्भ में इस बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। वर्ष 2014 में 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरूआत करते हुए अब हमारे पास 1.5 लाख किलोमीटर राजमार्ग हैं और जल्द ही इनके 2 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। आगामी भारतमाला कार्यक्रम सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क सड़कों को जोड़ेगा, आर्थिक गलियारों, अन्तर-गलियारों और फीडर रूट्स का विकास करेगा, राष्ट्रीय गलियारों के सम्पर्क में सुधार लाएगा। तटीय और बंदरगाह सम्पर्क सड़कों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का निर्माण करेगा। इसका आशय है कि देश के समस्त क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजमार्गों तक सुगम पहुंच होगी।

सड़क सम्पर्क का निर्माण करने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पिछड़े और आंतरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असम में ढोला सादिया सेतु जैसे पुल और जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशरी सुरंग जैसी अत्याधुनिक सुरगें, दुर्गम स्थानों की दूरियों को कम कर रहे हैं और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच को ज्यादा सुगम बना रहे हैं। वडोदरा-मुम्बई,बेंगलूरू-चेन्नई और दिल्ली-मेरठ मार्ग जैसे यातायात के अधिक दबाव वाले गलियारे विश्वस्तरीय,एक्सेस कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज की इंतजार में हैं, जबकि चार धाम और बौध सर्किट जैसे धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक यात्रा त्वरित और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी।

राजमार्गों के किलोमीटर बढ़ाने के अलावा, हम उन्हें यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए,एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सड़कों के डिजाइन में सुरक्षा की विशेषताएं शामिल करना,दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को दुरुस्त करना, सड़कों पर उचित संकेतक, ज्यादा प्रभावी कानून, वाहनों से संबंधित सुरक्षा के बेहतर मानक,चालकों का प्रशिक्षण, बेहतर ट्रामा केयर और जनता में जागरूकता बढ़ाना शामिल हैं। सेतु भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी रेलवे फाटकों को ओवर ब्रिज या अंडर पास से बदला गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी पुलों पर ढांचागत रेटिंग सहित एक इन्वेन्ट्री तैयार की जा रही है, ताकि उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य समय पर किया जा सकें।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना है। विधेयक में सख्त जुर्माना, वाहनों की उपयुक्ता के प्रमाणीकरण और वाहन चालकों को लाइसेंस देने जैसे विषयों को कम्प्यूटर द्वारा पारदर्शी बनाना, मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करना, कानूनी प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का समावेश किया गया है।

प्रदूषण की समस्या को कम करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया है। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाना, 01 अप्रैल, 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन नियमों को अपनाना, स्थानीय आबादी के सहयोग से राजमार्गों पर वृक्षारोपण तथा इलेक्ट्रनिक टोल क्लेक्शन प्रक्रिया को लागू करना शामिल है ताकि टोल प्लाजा के ऊपर वाहनों को कम समय तक इंतजार करना पड़े। इथेनाल, बायो-सीएनजी, बायो-डीजल, मीथेनाल और बिजली के इस्तेमाल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रायोगिक स्तर पर इन वैकल्पिक इधनों को कुछ शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सस्ते और हरित जल यातायात की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लम्बी तटरेखा और 14 हजार से अधिक लम्बे जलमार्गों का सागरमाला कार्यक्रम के जरिये क्षमता का आकलन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। सागरमाला के तहत बंदरगाहों के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास के जरिये बंदरगाहों के आसपास उद्योग लगाने का विचार है। इस विचार के तहत बंदरगाह संरचना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सड़क, रेल तथा जलमार्गों के जरिये अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही तटीय समुदायों का विकास किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि 35000- 40000 करोड़ रुपये की वार्षिक लाजिस्टिक बचत के अलावा निर्यात लगभग 110 अरब अमेरिकी ड लर तक बढ़ जाएगा तथा एक करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। अगले 10 वर्षों के दौरान सागरमाला द्वारा घरेलू जलमार्गों की हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कई जलमार्गों पर काम चल रहा है। इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नौवहन क्षमता का विकास किया जाएगा। गंगा नदी पर विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य हल्दिया से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को विकसित करना है ताकि वहां 1500-2000 टन जहाजों का नौवहन हो सके। वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-स्तरीय टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। यहां अन्य आवश्यक संरचना का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। इसके विकास से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में माल का आवागमन होने लगेगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। अगले तीन सालों में 37 अन्य जलमार्गों को विकसित किया जाएगा।

राजमार्ग और जलमार्ग क्षेत्रों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा एकीकृत यातायात प्रणाली का विकास किया जा रहा है। जो इष्टतम मोडल और निर्बाध अंतर-मोडल सम्पर्कता पर आधारित है। इस संबंध में लाजिस्टिक एफिशियेन्सी इनहांसमेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है ताकि देश में माल यातायात की क्षमता में बढ़ोतरी हो। इसमें 50 आर्थिक गलियारों,फीडर रूटों का उन्नयन, 35 मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्कों का विकास शामिल है। इन पार्कों में भंडारण और गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनके अलावा विभिन्न यातायात माध्यमों के एकीकरण के लिए 10 अंतर-मोडल स्टेशनों का निर्माण भी किया जाएगा।

भारत में यातायात क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में वह बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय परिदृश्य में यह क्रांति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके प्रकाश में हम यह आशा करते हैं कि इससे न केवल देश का तेज विकास होगा, बल्कि अब तक वंचित रहे क्षेत्रों और लोगों तक विकास के लाभ पहुंचेंगे।

गीताजंली वर्मा की पेंटिंग को पदम भूषण राम वी सुतार के हाथों 'आर्ट वैली अवार्ड' प्रदान

शिमला/शैल। नई दिल्ली के सुल्तानपुर में स्थित गांधी आर्ट गैलरी में मूंगा फाउंडेशन कीओर से आयोजित आर्ट वैली कंपीटीशन एंड एग्जिबिशन (आर्ट वैली प्रतियोगिता व प्रदर्शनी)2017 में गीताजंली वर्मा की पेंटिंग को आर्ट वैली अवार्ड से नवाजा गया हैं। गींताजंली वर्मा को ये अवार्ड पदमश्री व पदमभूषण से अलंकृत देश के विख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार ने एक सादे व गरिमापूर्ण समारोह में प्रदान किया। आर्ट वैली अवार्ड के अलावा गीतांजली वर्मा को दस हजार रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया।

अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए गीताजंली वर्मा ने कहा कि ये राज्य से बाहर राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रदर्शनी थी व पहली ही प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग को अवार्ड के लिए चुना गया। इसके अलावा पदम भूषण अलकृंत विख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार से अवार्ड लेना उनके लिए गौरव की बात हैं।

मूंगा फाउंडेशन की ओर से आयोजित आर्ट वैली कंपीटीशन एंड एग्जिबिशन (आर्ट वैली प्रतियोगिता व प्रदर्शनी) 2017 में देश भर से चार दर्जन के करीब कलाकारों ने अपने पेटिंग्ज को प्रदर्शित किया गया था।

गीताजंली वर्मा हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अर्की तहसील की गांव पलानियां की रहने वाली हैं। उसने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 2016 में विजुअल आर्ट में एमए की डिग्री ली।

गीताजंली के अलावा वाराणसी के रतन दीप चक्रवर्ती और दिल्ली के रवजोत सिंह को भी आर्ट वैली अवार्ड प्रदान किया गया।

पदम भूषण अलंकृत राम वी सुतार ने इन दोनों को भी दस-दस हजार रुपए का कैश प्राइज दिया। इसके अलावा बाकी सभी कलाकारों को मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया। दस-दस हजार रुपए का कैश प्राइज नाइन फिश आर्ट गैलरी के सौजन्य से दिया गया।

विख्यात मूर्तिकार सुतार ने समारोह में आए सभी कलाकारों से कहा वो प्रकृति का अवलोकन किया करें व जो देखा उसे ध्यान में रखें । उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास करने से कोई भी उंचाई हासिल की जा सकती हैं। राम वी सुतार को 1999 में पदमश्री व 2016 में पदम भूषण से नवाजा गया था।

इस मौके पर मूंगा फाउंडेशन के फाउंडर जयेश शर्मा ने कहा कि फाउंडेशन आगे से ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा व देश के कलाकारों की कलाकृतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष सती से बड़ा गद्दी बोर्ड का अध्यक्ष,ज्यादा फॉलोवर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को लेकर सफाई देते हुए कहा हैं कि सती से बड़ा तो गद्दी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा अध्यक्ष सतपाल सती की तुलना गद्दी सभा के अध्यक्ष से कर दी थी।

इस पर भाजपा ने तूफान खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस पर सफाई दी व कहा कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। उन्होने तो ये कहा कि भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सती से बड़ा तो गद्दी बोर्ड का अध्यक्ष है। उन्होंने कहा उनका मतलब ये था कि गद्दी बोर्ड के अध्यक्ष के सती से ज्यादा फोलोवर हैं।

वीरभद्र ने कहा कि गद्दी कल्याण बोर्ड का गठन भी उनकी सरकार ने किया वो गद्दी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

याद रहे कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं। ये सती को लेकर कहा था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विवादास्पद देने के मशहूर रहे हैं।

दलित स्वाभिमान सम्मेलन में 600 से अधिक लोगों भाजपा में शामिल

हमीरपुर /शैल। हमीरपुर में दलित स्वाभिमान सम्मेलन में दलित समाज के 600 से अधिक लोगों ने भाजपा में शामिल होकर स्पष्ट कर दिया की प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार पार्टी की गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति के लोगों, शोषित एवं पीड़ित वर्ग, जनजातीय, पिछड़े लोगों को समाज में आगे बढाने और बराबरी का हक देने के लिए काम करने की नीति पर दलित समाज के लोगों ने विश्वास की मोहर लगा दी है। कार्यक्रम में इतनी अधिक संख्या में भाजपा में शामिल होने वाले लोगों को देख कर भाजपा नेतृत्व गदगद था तो वहीं भाजपा में शामिल हुए नये सदस्य भी उत्साहित थे। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों पार्टी का पटका पहन कर हर व्यक्ति प्रो. धूमल के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। लोग लम्बी लम्बी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इन्तजार कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी में नये सदस्यों का स्वागत किया।

बहरहाल पार्टी को मजबूत होता देख पार्टी का नेतृत्व खुश हैं पार्टी ज्वाइन करने वाले भी खुश हैं की वर्षो तक वोट के नाम पर चलने के बाद भाजपा नेतृत्व से उम्मीद की किरण जागी है। समुदाय के लोग इसलिए भी आशावान है कि भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी कई योजनाओं से न केवल दलित समाज के लोगों को लाभ मिला बल्कि जीवन भी बेहतर स्थिति में पहुंचा है।

हमीरपुर तक शीघ्र पहुंचेगी ट्रेन

हमीरपुर/शैल। ऊना और हमीरपुर के बीच दौड़ने वाली ट्रेन के सपने को जल्द हकीकत में बदलने के लिए रेलवे ट्रैक के विकास को उत्तर रेलवे ने युद्धस्तर पर कारवाही चलाई हुई है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे के मुख्य-अभियन्ता ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय से ऊना हमीरपुर के बीच 50 किमी लम्बी ब्रॉड गेज नयी रेल लिंक के नये सरेखण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत अनुमान के लिए निविदाएँ आमन्त्रित की हैं। उत्तर रेलवे इस नये रेल लिंक को शीघ्र विकसित करने के लिए सक्रिय हो गयी है। हमीरपुर लोकसभा के सांसद

अनुराग ठाकुर के लगातार प्रयासों से यह कार्य प्रगतिपर है। बकौल अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों को रेलवे से जोड़ना उनका सपना है, जिसको वह शीघ्र पूरा करेंगे।

रेलवे लाइन को पूरा करने के काम को मिली इस गति से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपाईयों सहित स्थानीय जनता चहकी हुई है। इस रेलवे लाइन से जहां यातायात और यात्रा दोनों ही सुगम होंगे वहीं पर्यटन, कारोबार और रोजगार की दृष्टि से भी यह रेल लाइन मील का पत्थर साबित होगी।

वीरभद्र सिंह को चुनाव में हराने के लिये पूरी ताकत लगायेगा युवा मोर्चा :अरुण धूमल

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर में भाजयुमो की आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए युवा भाजपा नेता अरुण धूमल ने कहा की वीरभद्र सिंह प्रदेश में जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे युवा मोर्चा पूरा जोर लगा कर उन्हें उसी विस में हराएगा। अरुण धूमल ने कहा की प्रदेश के हालात

बदतर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पिछले पांच सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल हो गया है उसी कारण युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए युवा मोर्चा को अपने जोश को आक्रोश के रूप में बदलना पड़ा। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा सडकों पर उतर कर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है।

अरुण धूमल ने कहा की प्रदेश में वन माफिया फैला हुआ है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही चंबा से लेकर शिमला तक जंगल कट गये। प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। एक इमानदार गार्ड ने आवाज उठाने की हिम्मत की तो जंगल में उसकी लाश पेड़ पर उलटी टंगी मिली। कहा गया की आत्महत्या की। यह कैसे हालात प्रदेश में हो गये हैं। जनता की मांग को कि गार्ड की हत्या की सीबीआई जांच हो को सरकार ने नहीं माना। प्रदेश में ना जाने कितनी जगह जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं अपराध हो रहे हैं। उना में 37 महीने के बच्चे को घर से नकाब पोश ले उड़े, बाद में उसकी लाश मिली। शिमला में पेयजल के टैंक में बच्चे का नर कंकाल मिला। हमीरपुर का आदित्य डेढ़ साल से लापता है कोई सुराग प्रदेश की कानून व्यवस्था को उसका नहीं मिला है। अरुण धूमल ने कहा की प्रदेश की निक्कमी और नालायक सरकार के कारण प्रदेश की जनता आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।

अरुण धूमल ने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा की सुन लें वीरभद्र सिंह आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे युवा मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगा कर आपको उसी विधानसभा में हराएगा। हम महामहिम महोदय राज्यपाल से अपील करते हैं कि इस भ्रष्ट और निकम्मी नालायक सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि अति शीघ्र प्रदेश की जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर नयी सरकार चुने जो प्रदेश वासियों को सुरक्षित माहोल दे सके।

सुक्खू प्रताड़ना के सदमे से सही गलत का फर्क भूल गये हैं:विजय अग्निहोत्री

हमीरपुर/शैल। जनहित का पाठ स्वयं पढ़ें और प्रदेश सरकार को पढ़ाएं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और संगठन की ताकत भाजपा से सीखें। नादौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने प्रेसविज्ञप्ति में कांग्रेस प्रदेशाधयक्ष के ब्यान पर पलट वार करते हुए यह बात कही जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने लोगों का दुःख दर्द समझने और जनहित की बात कही थी। भाजपा नेता ने कहा की सुखविंदर सुक्खू उनको मिल रही प्रताड़ना से सही और गलत का फर्क भूल गये हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भले ही कांग्रेस सरकार में फैले भ्रष्टाचार और प्रदेश में चरमराई हुई कानून व्यवस्था के प्रति आँखें मूँद लीं हों लेकिन भाजपा भय एवं असुरक्षा के माहौल में जी रही प्रदेश की जनता को सत्ता की भूख के लिए बेहाल नहीं छोड़ेगी। जबकि सत्ता के मजे ले रहे कांग्रेस के मुखिया सहित तमाम कांग्रेस नेता प्रदेश में चल रहे कुशासन का विरोध नहीं कर पा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष हताशा का नाम देकर जिन प्रदर्शनों को कम आंक रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए की प्रदेश की जनता और युवा वर्ग ने भी इन प्रदर्शनों में बराबर की उपस्थिति दर्ज करवाई है।

विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस की निकम्मी और नालायक सरकार को प्रदेश से उखाड़ फैंकने का पूरा पूरा मन बना लिया। कांग्रेसियों को इस बात का अंदाजा पहले ही लग चुका है तभी एक तरफ पांच साल सत्ता सुख भोगने वाला और भ्रष्टाचार के मुकद्दमों में बेल पर चल रहा मुख्यमंत्री जाती सरकार में बिना किसी बजट प्रावधान के ताबड़तोड़ घोषणाएं शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा प्रताड़ित और उपहास का केंद्र बिंदु बने प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के प्रदर्शनों का विरोध कर रहे हैं। जबकि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई को लेकर तब सड़कों पर उतरी है जब प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, और प्रदेश की जनता भी इन प्रदर्शनों में भाजपा का पूरा साथ दे रही है।

स्वाधीनता सेनानियों को हिमाचलवासियों का शत्-शत् नमन

71वें स्वाधीनता दिवस

के पावन अवसर पर

आईए, हम प्रण लें
असंख्य स्वाधीनता सेनानियों के
प्राणों की आहुति से सश्रम अर्जित
आज़ादी की मूल भावना को समझते हुए
सत्य, अहिंसा व सद्मार्ग पर चल कर
प्रदेश व देश की उन्नति व खुशहाली में
अपना योगदान देंगे।

देश की आन, बान और
शान की ख़ातिर
अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले
स्वाधीनता सेनानियों को
प्रदेशवासियों का नमन।

-सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

न्याय मंच के आंदोलन को कंट्रोल करने से नहीं,पुलिस जांच पर उभरे संदेहों का निराकरण करने से होगी स्थिति सामान्य

शिमला/शैल। गुडिया गैंगरेप व मर्डर, फारेस्ट गार्डहोशियार सिंह के कातिलों को पकड़ने की मांग व लापता मेदराम की तलाश को लेकर आम आदमी की आवाज सता के गलियारों तक गुंजाने के लिए उतरी भीड़ को काबू करने के लिए वीरभद्र सिंह सरकार ने डीसी, एसपी व पुलिस बलों के अलावा फायर विभाग को मैदान में उतार दिया हैं।

शिमला में गुडिया गैंगरेप व मर्डर कांड के बाद पहली बार वीरभद्र सिंह सरकार ने आंदोलनकारियों को कट्रोल करने के लिए पुलिस को मैदान में उतारा हैं। इससे पहले आंदोलनकारी धारा 144 तोड़ कर मालरोड़ से सचिवालय जाते थे। चूंकि ये राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, तो शायद मंच ने टकराव का रास्ता नहीं अपनाया नहीं तो आज पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच भिड़ंत हो ही जाती।

मामूली घरों के इन तीनों पीडितों की ओर से न्याय की आवाज प्रदेश सरकार ने कितनी सुनी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुडिया गैंगरेप कांड की जांच में पुलिस की ओर से किए गए कारनामों के बाद सीबीआई जांच शुरू हो गई हैं।

जबकि करसोग में फारेस्ट गार्ड होशियार सिंह के कत्ल में प्रदेश पुलिस किस तरह की जांच कर रही हैं, ये हाईकोर्ट की टिप्पणियों से जाहिर हो चुका है। मेदराम एक अरसे से लापता है, लेकिन उसे तलाशने में पुलिस नाकाम हैं।

यहां ये महत्वपूर्ण है कि गुडिया गरीब घर से थी। वो बीपीएल परिवार से थी। फारेस्ट गार्ड हाशियार सिंह को उसकी दादी ने पाला था। उसके मां बाप मर चुके थे। मुश्किल से वो फारेस्ट गार्ड लगा था व अभी नौकरी में साल भी नहीं हुआ था कि उसका कत्ल हो गया। उसकी डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ हैं। अब उसकी बूढ़ी दादी ही बची है। यही स्थिति मेदराम की भी है, वो भी एक अरसे से लापता है।

सरकार व एजेंसियों की नाकामियां कभी उजागर नहीं होती अगर समाज आगे आकर आवाज नहीं उठाता। इन तीनों परिवारों में ऐसा कोई भी नहीं था जिनकी फरियाद सरकार व एजेंसियों के कानों तक पहुंचती। गुडिया गैंगरेप कांड व होशियार सिंह मामले में पुलिस ने जो कारनामे किए, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। उस आक्रोश में भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी सब साथ थे। अब सरकार ने पुलिस व प्रशासन को सड़कों पर उतार दिया है।

गुडिया न्याय मंच के बैनर तले इन परिवारों के परिजन न्याय की आस में इसलिए सड़कों पर है ताकि एजेंसियां कोई और गुल न खिला दें। लेकिन वीरभद्र सरकार उस आवाज को भी कंट्रोल करने पर तुल गई है।

गुडिया न्याय मंच के बैनर तले जब भारी भीड़ सीटीओ से मालरोड होते सचिवालय के लिए जाने के लिए एकत्रित हुई तो महिला डीसी रोहन ठाकुर, एसपी सौम्या सांबशिवन पूरी विनम्रता के साथ भीड़ के आगे आ गए और गुडिया न्याय मंच के प्रतिनिधियों कुलदीप तनवर, राकेश सिंघा, संजय चौहान समेत बाकियों से आग्रह किया कि वो धारा 144 न तोड़े व वाया लोअर बाजार जाएं। चूंकि डीसी व एसपी मौके पर थे तो बाकी अफसर भी साथ ही आ गए।

लेकिन इससे पहले सीटीओ पर बैरीकेटस लगा पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखे थे। महिला पुलिस, पुरूष पुलिस के अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी तैनात कर दी गई। ये साफ संदेश था। ताकि अगर मंच के बैनर तले एकत्रित लोगो ने बैरिकेटस तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की तो बल इस्तेमाल करने का पूरा इंतजाम था।

बहरहाल, ये सारे इंतजाम देखते हुए, पीडितों की लड़ाई कहीं और दिशा न पकड़ लें, मंच ने टकराव न करने का फैसला लिया। नाज के पास भीड़ सचिवालय के बजाय माल रोड़ की ओर से मुड़ जाए पुलिस ने वहां भी बेरीकेटस लगा दिए। इससे भीड़ में गुस्सा जरूर आया व नाज पर जमकर नारेबाजी की गई लेकिन भीड़ आगे सचिवालय की ओर बढ़ गई। भीड़ के नाज पर रुक जाने पर मंच के एक पदाधिकारी ने बाद में कहा भी कि समझौता हो गया है, इसलिए यहां क्यों रोका होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये ठहराव केवल गुस्सा जाहिर करने के लिए था। शुक्र है कि मंच के पदाधिकारियों ने टकराव का रास्ता नहीं अपनाया अन्यथा वीरभद्र सिंह सरकार की फजीहत और हो जाती।

लेकिन सरकार के लिये स्थिति अभी सुखद नही है क्योंकि फारेस्ट गार्ड होशियार सिंह के मामलें में अब उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए सरकार से दो टूक पूछा है कि यह मामला भी सीबीआई को क्यों न सौंप दिया जायें यह नौवत इसलिये आई है क्योंकि पुलिस जांच की रिपोर्ट आम आदमी के गले नही उतर पायी हैं हर संवेदनशील मामले में पुलिस की नीयत और नीति गंभीर सन्देहों में घिरती जा रही है इससे सरकार और खासतौर पर स्वयं मुख्यमन्त्री और उनके सचिवालय की विश्वनीयता सवालों में आ खड़ी हुई है। अब विधानसभा चुनावों को सामने रखते सरकार को अपनी विश्वनीयता बहाल करने के लिये या तो इन मामलों के गुनाहागारों को पकड़ कर या फिर संबद्ध पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के अतिरिक्त और कोई कारगर विकल्प नही बचा है क्योंकि गुड़िया मामलें में पुलिस की कार्यप्रणाली पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर मुख्यमन्त्री के फेसबुक पेज पर कथित अपराधियों के फोटो आने फिर हटा लिये जाने से जो सन्देह उभरे है वह अभी तक अपनी जगह बने हुए है। यदि सीबीआई भी इन सन्देहों पर से पर्दा न हटा पायी तो जनाक्रोश को एक बार सड़कों पर आने से कोई नही रोक पायेगा और वह स्थिति सरकार के लिये बहुत घातक सिद्ध होगी यह तय है।

एचआरटीसी के आर.एम. के खिलाफ शिमला पुलिस का केस निकला फ्राड

शिमला/शैल। शिमला पुलिस ने 30 अप्रैल को शोघी में नाका लगाकर एचआरटीसी के सोलन में तैनात आर एम महेन्द्र सिंह को चार किलो चिट्टे के साथ पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसे बालूगंज थाना में लाया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गयी। जो चिट्टा पकड़ा था उसे जुंगा की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिये भेजा गया। जुन्गा के अतिरिक्त इस चिट्टे के नमूने हैदराबाद की लैब में भी भेजे गये थे। यह नमूने भेजने के बाद महेन्द्र सिंह को कैंथु जेल भेल दिया गया। जब चार किलो चिट्टे के साथ प्रदेश की परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर के पकड़े जाने की खबर मीडिया में उठी तब इस संद्धर्भ में एक जनहित याचिका भी प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हो गये क्योंकि अपने में ही यह एक बड़ा कांड था। उच्च न्यायालय में यह याचिका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल जस्टिस अजय मोहन गोयल की खण्डपीठ में सुनवाई के लिये आई। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले का संज्ञान लिये जाने के बाद पुलिस को अपनी जांच में तेजी लानी पड़ीं लेकिन जैसे ही यह मामला आगे बढ़ा पुलिस का सारा केस एकदम आधारहीन और झूठ का पुलिंदा प्रमाणित हुआ और परिणाम स्वरूप महेन्द्र सिंह न केवल इस मामले से बाईज्जत बरी हुए बल्कि एचआरटीसी को उनके निलंबन के आदेश भी वापिस लेने पड़े और उन्हें नौकरी से बहाल करना पड़ा। महेन्द्र सिंह ने इस मामले में बरी होने के बाद एक पत्रकार सम्मेलन करके शिमला पुलिस पर एक पूरी तरह फ्राड केस खड़ा करने के लिये संबधित अधिकारी के खिलाफ 50 लाख का मानहानी का दावा दायर करने का ऐलान किया है।

शिमला पुलिस द्वारा एक अधिकारी के खिलाफ इस तरह का फ्राड मामला खड़ा करने के आरोपों ने पूरी व्यवस्था पर कोई गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। पुलिस की इस ज्यादती के कारण महेन्द्र सिंह को 72 दिन जेल में गुजारने पड़े हैं। बेगुनाह होते हुए इस

तरह के इल्जाम में 72 दिन जेल में काटने पर मेहन्द्र सिंह और उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। महेन्द्र सिंह के मुताबिक 30 अप्रैल रविवार को वह अपनी गाड़ी से नालागढ़ से शिमला आ रहे थे और शाम को 7:30 बजे के करीब शोघी पहुचे। गाड़ी में उनके साथ एक राजीव नाम का व्यक्ति भी था। इस राजीव को किसी विकास का फोन आया जिसने कहा कि उससे मिलना ओर वह पंप के समीप है यह संदेश मिलने पर उन्होने गाड़ी मोड़ी ओर पंप पर चले गये। वहां पहुंचने पर गाड़ी से उतरे और पेशाब करने चले गयें जैसे ही वह वापिस आये तो सीआईए स्टाफ ने उनसे धक्का-मुक्की शुरू कर दी और चैक पोस्ट में ले गये और उनके पास वहां पहले ही एक बैग मौजूद था। महेन्द्र सिंह ने उन्हे अपना पहचान पत्र भी दिखाया लेकिन कोई असर नही हुआ। इसी नोक झोंक में नौ बज गये व साढे नौ बजे के करीब उन्हे बालूगंज थाना में ले आये। थाना में डीएसपी रत्न सिंह ने उन्हे बहुत टार्चर किया। लेकिन पुलिस ने अपने रिकार्ड में महेन्द्र सिंह को रात साढ़े बारह बजे शोघी में नाके पर खड़ा पकडा हुआ दिखाया है और उनसे चार किलो चिट्टा बरामद किया बताकर सुबह चार बजे गिरफ्तारी दिखाई। एफआरआई में यह भी कहा गया है कि महेन्द्र सिह ने बैग को गाड़ी में छुपाने की कोशिश की और ड्रावर ने यह बैग आरएम का ही है महेन्द्र सिह के मुताबिक उनकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गाड़ी 7:30 बजे के करीब शोघी में है और उसके बाद साढ़े नौ से लेकर सुबह तक गाड़ी बालूगंज थी। गाड़ी रात दस बजे के बाद चली ही नहीं ऐसे में जब गाड़ी चली ही नही तो पुलिस ने रात बारह बजे के बाद उनकी गाड़ी शोघी में कैसे पकड़ी? जीपीए की रिपोर्ट से पुलिस की सारी रिपोर्ट का पर्दाफाश हो गया। महेन्द्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे लो लाख रूपये की मांग की थी।

पुलिस ने जो कथित चार किलो चिट्टा महेन्द्र सिंह सेना के में पकड़ा दिखाया था उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय ने तलब कर ली थी। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जो नमूना जांच के लिये भेजा था वह अमोनियम कार्बन और अमोनियम वायोकार्बोनेट था जो वेकरी में काम आता है हैरदावाद लैब से भी यही रिपोर्ट आयी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सारा केस धराशाही हो गया और महेन्द्र सिंह स्पैलज जज की अदालत से वरी हो गया। महेन्द्र सिंह ने संबद्ध पुलिस अधिकारी के खिलाफ 50 लाख का मानहानि का दावा करने और अगले 15 दिनों में इस मामलें में और खुलासा करने का ऐलान किया है।

जीपीएस की रिपोर्ट से पुलिस की सारी रिपोर्ट के पर्दाफाश से यह प्रमाणित हो जाता है कि पुलिस एकदम झूठा केस खड़ा कर रही थी। पुलिस की नीयत और कार्य प्रणाली दोनों पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जब नीयतन एक झूठा केस बना रही थी तब इसमें भी चिट्टे की जगह बेकरी पाऊडर इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका अर्थ है कि गल्त काम भी गल्त तरीके से किया जा रहा था। इस पर अब पुलिस के शीर्ष प्रशासन और मुख्यमन्त्री पर सवाल आयेगा कि पुलिस का यह झूठ सामने आने के बाद दोषीयों के खिलाफ क्या कारवाई की जाती है।